साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 12, अंक : 32 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 5 अगस्त 2026 से 11 अगस्त 2026 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

जीन एडिटिंग के जरिए एशिया-अफ्रीका के छोटे किसानों के लिए विकसित होंगी नई जलवायु रोधी फसल किस्में

नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों के बीच इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (आईसीआरआईएसएटी) को सीआरआईएसपीआर-सीएस9 जीन एडिटिंग तकनीक के इस्तेमाल का दीर्घकालिक लाइसेंस मिल गया है। इस समझौते के बाद आईसीआरआईएसएटी एशिया और अफ्रीका के छोटे किसानों के लिए ऐसी फसल किस्में विकसित करने में तेजी ला सकेगा, जो सूखा, गर्मी, कीट और बीमारियों जैसी चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकें।

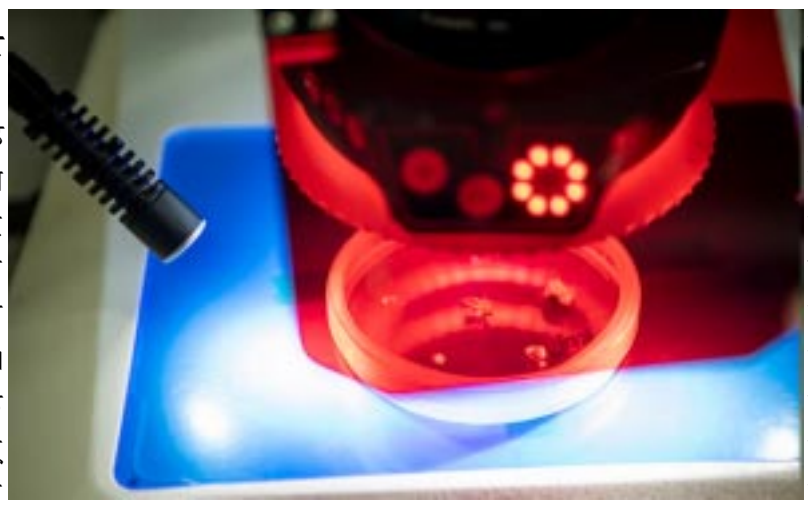

यह मानवीय लाइसेंस समझौता कॉर्टेवा और द ब्रॉड इंस्टीट्यूट इंक के साथ किया गया है। इसके तहत आईसीआरआईएसएटी को अनुसंधान, फसल सुधार और किसानों तक नई जीन एडिटेड किस्मों को पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में सीआरआईएसपीआर-सीएस9 तकनीक का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। आईसीआरआईएसएटी के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने इस समझौते को संस्थान और छोटे किसानों के लिए एक परिवर्तनकारी मानवीय उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा, यह नई क्षमता ऐसी व्यावहारिक फसल तकनीकों के विकास को गति देगी, जो खाद्य सुरक्षा मजबूत करेंगी, साथ ही आजीविका सुधारेंगी और एशिया तथा अफ्रीका में अधिक लचीली कृषि प्रणालियां बनाने में मदद करेंगी। सीआरआईएसपीआर-सीएस9 तकनीक को कृषि क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नई तकनीकों में से एक माना जा रहा है। पारंपरिक फसल प्रजनन में किसी वांछित गुण को विकसित करने में कई वर्ष लग सकते हैं, जबकि जीन एडिटिंग वैज्ञानिकों को पौधों के जीन में सटीक बदलाव करने की सुविधा देती है। इससे ऐसी किस्में विकसित की जा सकती हैं जिनमें कम पानी में उत्पादन बनाए रखने, बढ़ते तापमान को सहने, रोगों से बचाव और बेहतर पोषण जैसे गुण हों। खास बात यह है कि जीन एडिटिंग में किसी दूसरी प्रजाति का डीएनए शामिल नहीं किया जाता, बल्कि पौधे के मौजूदा जीन में ही बदलाव किए जाते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल आईसीआरआईएसएटी अपनी प्रमुख फसलों में करेगा। इनमें ज्वार, मोती बाजरा और अन्य बाजरा किस्में, चना, अरहर और मूंगफली जैसी फसलें शामिल हैं। ये फसलें एशिया और अफ्रीका के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में लाखों छोटे किसानों की आजीविका का आधार हैं। आईसीआरआईएसएटी का कहना है कि यह समझौता उसकी जीनोमिक्स, फसल प्रजनन, फीनोमिक्स, बीज प्रणालियों और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी को और मजबूत करेगा। इससे प्रयोगशालाओं में विकसित वैज्ञानिक खोजों को किसानों के खेतों तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेज हो सकेगी। कॉर्टेवा की जैव प्रौद्योगिकी उपाध्यक्ष डॉ. वेंडी सर्निक ने कहा, एशिया तथा अफ्रीका के छोटे किसानों तक जीन एडिटिंग तकनीक पहुंचाने में मदद करने पर गर्व है। उन्होंने आगे कहा, हम मिलकर ऐसी फसलें विकसित करने के लिए काम करने की उम्मीद रखते हैं जो चरम मौसम की घटनाओं, कीटों और बीमारियों का बेहतर सामना कर सकें। इससे किसानों को अपने समुदायों का पोषण करने और अधिक लचीली वैश्विक खाद्य प्रणाली बनाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के दौर में खेती के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्पादन बनाए रखते हुए संसाधनों का संरक्षण करना है। जीन एडिटिंग जैसी तकनीकें कम जमीन और सीमित संसाधनों में अधिक उत्पादन देने वाली फसल प्रणालियों के विकास में मदद कर सकती हैं। हालांकि, इसके व्यापक इस्तेमाल के लिए जैव सुरक्षा मानकों, नियामकीय प्रक्रियाओं और छोटे किसानों तक तकनीक की पहुंच सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा।

समृद्ध मध्यप्रदेश के लिए सेवा और सुशासन ही हमारा मूल विकास मंत्र - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को जबलपुर को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि नगर निगम जबलपुर अगले एक वर्ष में मेट्रोपोलिटन सिटी बनेगा। उन्होंने मौके पर ही संबंधितों (कमिश्नर, कलेक्टर एवं अन्य) को जल्द से जल्द जबलपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी का ड्रॉफ्ट प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सेवा हमारी सरकार का दायां और सुशासन बायां हाथ है। हम मध्यप्रदेश के विकास प्रदेश के नागरिकों की सुख-समृद्धि और सेवा के प्रति संकल्पित है। सेवा और सुशासन ही हमारे लिए समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण का मूल और वास्तविक विकास मंत्र है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने प्रदेश की जनता से विकास का सच्चा वादा किया है। आज प्रदेश में चहुंओर विकास की बहार है। %सच्चा वादा, पक्का काम% हम जो भी कहते हैं, वो करके भी दिखाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को जबलपुर के गीता भवन परिसर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-भूमिपूजन का 11 लाख पौधे लगाने के महा अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।

दुनिया के मौसम पर रहेगा अल नीनो का असर-डब्ल्यूएमओ

न्यूयार्क। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने कहा है कि अल नीनो लगातार मजबूत हो रहा है और अगस्त से अक्टूबर 2026 के दौरान दुनिया के मौसम पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। इसके कारण दुनिया के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने का अंदेशा है। साथ ही कई क्षेत्रों में बारिश के पैटर्न में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार अल नीनो के साथ हिंद महासागर में बनने वाला सकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल भी मौसम को प्रभावित करेगा।

डब्ल्यूएमओ के अनुसार, आने वाले महीनों में दुनिया के अधिकांश भूभाग पर सामान्य से अधिक तापमान रहने के आसार हैं। अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, अरब प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका, कैरेबियन, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के बड़े हिस्से और न्यूजीलैंड में गर्मी सामान्य से ज्यादा रह सकती है। समुद्रों का तापमान भी पहले से काफी अधिक बना हुआ है, जिससे मौसम की चरम घटनाएं बढ़ सकती हैं। अल नीनो का असर केवल तापमान तक सीमित नहीं रहेगा। इससे कई क्षेत्रों में बारिश का स्वरूप भी बदल सकता है। डब्ल्यूएमओ के अनुसार, पूर्वी अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिणी यूरोप, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण-पूर्वी दक्षिण अमेरिका में सामान्य से अधिक बारिश होने की आशंका है। वहीं भारत सहित पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के दक्षिणी भाग, कैरेबियन के कुछ हिस्सों, उत्तर-पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और उत्तरी यूरोप में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मजबूत अल नीनो और सकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल मिलकर कई क्षेत्रों में सूखा, बाढ़ और जंगलों में आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ा सकते हैं। लंबे समय तक चलने वाली गर्मी से खेती, जल संसाधनों और लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। कई देशों में पानी की कमी और फसलों को नुकसान होने की आशंका भी जताई गई है। रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के हवाले से कहा गया है कि अल नीनो अब केवल आने वाला खतरा नहीं है, बल्कि इसका असर शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले ही बढ़ती गर्मी, समुद्रों के रिकॉर्ड तापमान और भीषण जंगलों की आग जैसी घटनाओं का सामना कर रही है। ऐसे में जीवाश्म ईंधन का लगातार उपयोग इस संकट को और गंभीर बना रहा है। उन्होंने देशों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तेजी से कदम उठाने की अपील की। रिपोर्ट में डब्ल्यूएमओ की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा कि अल नीनो दुनिया की सबसे अधिक निगरानी की जाने वाली जलवायु घटनाओं में से एक है। हालांकि केवल मौसम का पूर्वानुमान देना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि सरकारें, संस्थाएं और आम लोग समय रहते तैयारी करें। यदि पहले से सही जानकारी मिल जाए तो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया है, जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का समुद्री तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। यह घटना आमतौर पर हर दो से सात साल के बीच होती है और करीब नौ से बारह महीने तक बनी रह सकती है। इसका असर केवल प्रशांत महासागर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया के कई देशों के मौसम पर पड़ता है। हर बार इसका प्रभाव अलग-अलग हो सकता है क्योंकि यह अन्य जलवायु प्रणालियों के साथ मिलकर काम करता है।

सोच समझ के दायरे पहले भी हिमाचल में सुदृढ़ थे, लेकिन अब सुक्खू सरकार ने पानी को महज पानी न मानते हुए, इसकी हर बूंद में हीरे-ज्वाहरात देखे

सोच समझ के दायरे पहले भी हिमाचल में सुदृढ़ थे, लेकिन अब सुक्खू सरकार ने पानी को महज पानी न मानते हुए, इसकी हर बूंद में हीरे-ज्वाहरात देखे हैं। यही वजह है कि न केवल किशाऊ बांध समझौते के बाद मुख्यमंत्री ने लाभ तक सीमित रहना सीखा और न ही पानी की अस्मिता को परवान चढ़ाने का अपना मकसद छोड़ा। किशाऊ बांध पहले ही कमाऊ बांध बन चुका है और अब इसे प्याऊ बांध बनाने का नवाचार हिमाचल ने शुरू किया है। यह आर्थिक हितों को हासिल करने का नवाचार है।

कहना न होगा कि पहले किसी मुख्यमंत्री ने इस स्तर तक आर्थिक अधिकारों का मोल तोल नहीं किया, बल्कि यह उचित समय है कि हम पंजाब पुनर्गठन की सियासी फाइल को स्वर्गीय वाईएस परमार के दौर से खोलें। हम पहले भी कह चुके हैं कि पंजाब पुनर्गठन से हिमाचल के लिए महज एक जमीन का टुकड़ा हासिल करके सारी शक्ति, हितों की पैरवी और न्याय की कसौटी छोड़ दी। तब की गंदी राजनीति ऊपरी और निचले हिमाचल की शिनाख्त करती रही या सारी सौदेबाजी, कर्मचारी व सेब लॉबी तक सिमट गई। न केवल परमार, बल्कि शांता कुमार भी कुछ हद तक लपेटे में आए। खैर सुक्खू सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत कदम उठाते हुए पहले किशाऊ को कमाऊ बना कर वार्षिक आय में 600 करोड़ की राशि डाली और अब इसे प्याऊ मानकर वर्षों की प्यास यानी पंजाब पुनर्गठन की इबारत खोल दी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उनकी मुलाकातें और अब वकालत का तर्क यह कि किशाऊ बांध का महत्त्व अगर कायम करना है, तो इसकी नींव के पत्थर पंजाब पुनर्गठन में हिमाचल की भागीदारी और लेनदारी सुनिश्चित करके ही लगेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले की नीति के तहत प्रदेश का कद व सम्मान बढ़ाया है, वरना हमारे पड़ोसी राज्य बराबरी की न बात करते या हिमाचली अधिकारों की नाफरमानी पर उतर आते हैं। कई पक्षीय वार्ताओं का रुख मोड़ते हिमाचल ने हरियाणा के दर्द को बांटने का जिम्मा उठाते हुए, एक बड़ा दांव खेला है।

इससे पूर्व सिंधु घाटी जल संधि की समाप्ति से हिमाचल के राष्ट्रीय तर्क मजबूत हुए हैं। हम पानी में समाधि या जल कब्रें बना कर खामोश क्यों रहें। ये तमाम बांध हमारे अधिकारों की कब्रें साबित न हों, इसलिए सुक्खू सरकार ने एक पलड़े पर किशाऊ बांध और दूसरे पर पंजाब पुनर्गठन के अधिकार रखे हैं, ताकि इंसाफ का तकाजा कायम रहे।

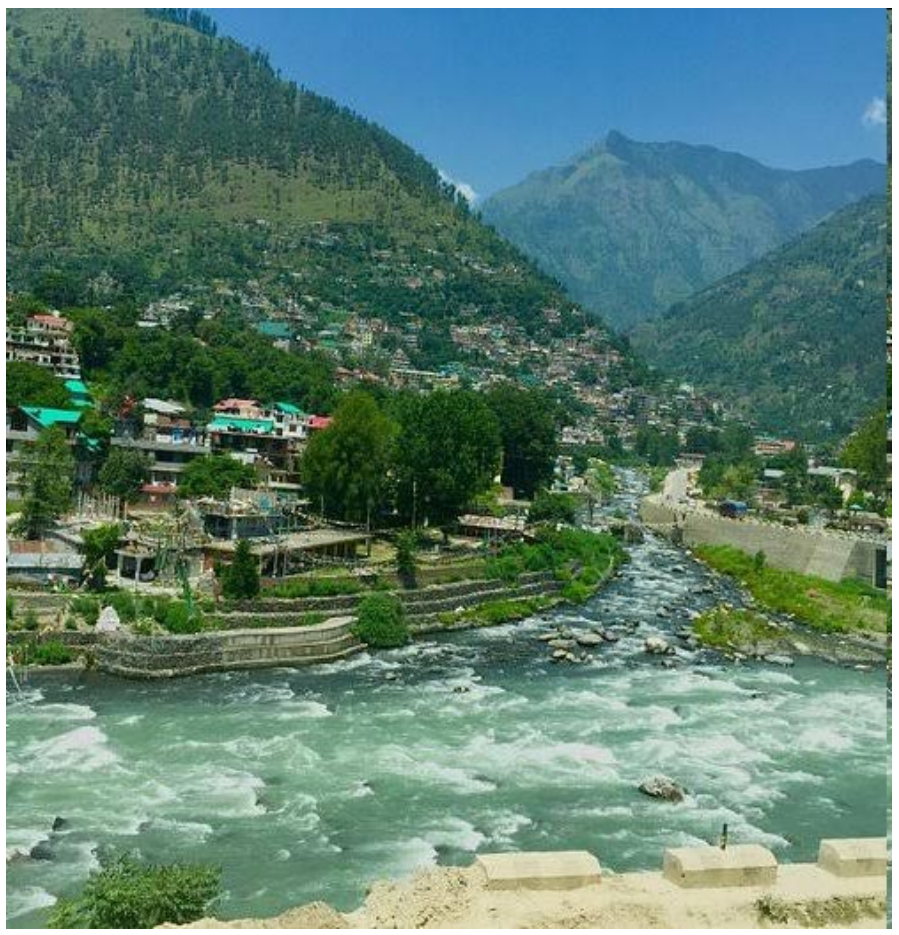

बीबीएमबी हमारी छाती पर लगातार मूंग नहीं दल सकता, इसलिए सुप्रीम फैसलों की दुहाई से निकले 7.19 प्रतिशत के हिसाब से लंबित 13.066 मिलियन विद्युत यूनिट का भुगतान या 4200 करोड़ की राशि तुरंत हिमाचल को मिले। यह आर्थिक अधिकारों की इंचें हैं जो किशाऊ बांध की शर्तों में मापी जा रही हैं। एक बार हरियाणा, पंजाब पुनर्गठन में हिमाचल का पक्ष अंगीकार करें तो तमाम जल वितरण के घाव धुलेंगे। राष्ट्रीय हित की किशाऊ बांध परियोजना के गले में घंटी बांध कर हिमाचल ने अपने आर्थिक हितों का अलार्म बजा दिया है, अब पंजाब को भी शानन विद्युत परियोजना पर अवैध कब्जा छोडऩा ही होगा। यही नहीं राष्ट्रीय संसाधनों और जल विद्युत परियोजनाओं की साझेदारी में हिमाचल को चालीस साल से उत्पादन कर रहे

दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के मरेलैंड्स में एच5 बर्ड फ्लू का पहला मामला, जून से अब तक देश में 74 संक्रमण, मोनार्टो सफारी पार्क में कड़े एहतियात

सिडनी। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के मरेलैंड्स इलाके में पहली बार खतरनाक एच5 बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, मोनार्टो क्षेत्र में मिले एक ग्रेटर क्रेस्टेड टर्न पक्षी में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। यह पक्षी उन छह संदिग्ध मामलों में शामिल था, जिनकी जांच शनिवार, एक अगस्त, 2026 को की गई थी। ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिपेयर्डनेस के अनुसार, राज्य में अब तक कई पक्षियों में इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा कई अन्य पक्षियों के नमूनों की जांच जारी है। विशेषज्ञों का कहना है इस बार फैल रहा एच5 वायरस सामान्य बर्ड फ्लू की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल सकता है और पक्षियों के लिए अधिक घातक साबित हो सकता है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में 40 पक्षियों में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी थी, जबकि 34 अन्य संदिग्ध मामलों की जानकारी है। जून में देश पहली बार सामने आने के बाद से अब तक पूरे ऑस्ट्रेलिया में इस घातक वायरस के 74 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

बर्ड फ्लू एक ऐसा वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। यह बीमारी पानी रहने वाले पक्षियों, शिकारी पक्षियों और घरेलू मुर्गियों जैसे कई प्रकार के पक्षियों में फैल सकती है। संक्रमित पक्षियों की मौत भी हो सकती है, जिससे वन्यजीवों और पोल्ट्री उद्योग पर बड़ा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, वायरस पक्षियों के शरीर के तरल पदार्थ, मल, पंख और संक्रमित जगहों के संपर्क से फैलता है। दूषित पानी, भोजन, मिट्टी या अन्य सतहों के जरिए भी इसका संक्रमण फैल सकता है। हालांकि बर्ड फ्लू का मुख्य असर पक्षियों पर होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अन्य जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। इससे समुद्री स्तनधारी, बिल्ली, सूअर, बकरी और कुछ अन्य जानवर प्रभावित हो सकते हैं। इंसानों में संक्रमण बहुत दुर्लभ है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि मौजूदा एच5 वायरस को लेकर इंसानों में सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने का कोई सबूत नहीं मिला है। फिर भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकार ने लोगों से कहा है कि वे बीमार या मृत पक्षियों को हाथ न लगाएं। अगर कोई संदिग्ध पक्षी दिखाई देता है तो उसकी जानकारी अधिकारियों को दें और संभव हो तो उसकी फोटो या वीडियो भी लें। लोगों से यह भी कहा गया है कि वे अपने पालतू जानवरों को संक्रमित या मृत पक्षियों से दूर रखें। रिपोर्ट के अनुसार, मोनार्टो सफारी पार्क के में पहले से ही बर्ड फ्लू से बचाव के लिए कई सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। आगे बताया गया कि पार्क कई वर्षों से इस तरह की स्थिति के लिए तैयारी कर रहा था। पार्क में संवेदनशील पक्षियों के रहने वाले स्थानों को सुरक्षित बनाया गया है। जंगली पक्षियों और वहां मौजूद जानवरों के बीच संपर्क कम करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल पार्क खुला है और पर्यटक यहां सुरक्षित रूप से आ सकते हैं। लेकिन लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी बीमार या मृत पक्षी को न छुएं और तुरंत इसकी सूचना दें। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की प्राथमिक उद्योग मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि राज्य के लोगों ने बर्ड फ्लू को लेकर अच्छी सतर्कता दिखाई है। आम लोगों की जानकारी, विशेषज्ञों की निगरानी और हवाई सर्वेक्षणों की मदद से संक्रमण के मामलों का जल्दी पता लगाया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार वन्यजीव विशेषज्ञों, उद्योगों और आम जनता के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि एच5 बर्ड फ्लू के खतरे को नियंत्रित किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सावधानी और समय पर सूचना देने से पक्षियों और वन्यजीवों की सुरक्षा में बड़ी मदद मिलेगी।

एमपी के इस टाइगर रिजर्व का नाम सामने आते ही चौंके अधिकारी

शिवपुरी उत्तर प्रदेश के आगरा में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वन्यजीव तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। टीम ने एक होटल में छापा मारकर 10 तेंदुओं की खाल और उनके सिर बरामद किए हैं। इस मामले में चार अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

आगरा में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। होटल में तेंदुओं की खाल का सौदा करने पहुंचे चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पूछताछ में शिवपुरी और मुरैना के जंगलों का नाम सामने आया है, हालांकि मध्य प्रदेश वन विभाग ने कहा है कि बरामद खालें किस क्षेत्र की हैं, इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। गिरफ्तार आरोपियों में हरियाणा निवासी सतपाल नाथ और भगत सिंह, मुरैना निवासी गब्बर तथा शिवपुरी निवासी भोगीराम आदिवासी शामिल हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया कि वे शिवपुरी के जंगलों और माधव नेशनल पार्क क्षेत्र से बेहद कम कीमत पर तेंदुओं की खाल खरीदकर दूसरे राज्यों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। आगरा के होटल में सौदा करते समय वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर पूरे गिरोह को पकड़ लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब वन विभाग, वाइल्डलाइफ एसओएस, वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और मध्य प्रदेश स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की संयुक्त टीमें नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि गिरोह किन-किन राज्यों में सक्रिय था और वन्यजीवों का शिकार कहां-कहां किया गया। इधर, माधव टाइगर रिजर्व के मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) उत्तम शर्मा ने कहा कि फिलहाल माधव टाइगर रिजर्व या शिवपुरी के जंगलों में तेंदुओं के शिकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बरामद खालें किस क्षेत्र से लाई गई हैं, इसका पता विस्तृत जांच और वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही चल सकेगा। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार एक साथ 10 तेंदुओं की खाल बरामद होना बेहद गंभीर मामला है। इससे संगठित वन्यजीव तस्करी के बड़े नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। आने वाले दिनों में जांच के आधार पर इस पूरे रैकेट से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

एक्सीडेंट में घायल मादा चिंकारा को खींचकर ले जा रहे थे आवारा कुत्ते

खरगोन (संवाददाता द्वारा)मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में इंसानियत और वन्यजीव संरक्षण की एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है। बड़वाह क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुई अनुसूची-1 में संरक्षित एक मादा चिंकारा को ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों के झुंड से बचाकर नई जिंदगी देने की पूरी कोशिश की, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद वह बेहतर उपचार के लिए इंदौर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ गई।

वन विभाग के पाडल्या वन रेंज के डिप्टी रेंजर कमल जोशी और वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट टोनी शर्मा के अनुसार, करीब तीन वर्ष की मादा चिंकारा माचलपुर खुर्द और बर्दिया बंजारी गांवों के बीच किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई थी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागी, लेकिन वहां आवारा कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया। इसी दौरान खेत से लौट रहे बंजारी निवासी रवि करोले की नजर घायल चिंकारा पर पड़ी। उन्होंने अन्य ग्रामीणों की मदद से तुरंत कुत्तों को खदेड़ा और चिंकारा की जान बचाई। अत्यधिक रक्तस्राव, एक सींग, एक पैर और जबड़े के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण चिंकारा दोबारा खड़ी नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने उसे पानी पिलाया और तुरंत डायल-112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही बड़वाह थाना पुलिस और वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा।

छोटे कदमों से जलवायु परिवर्तन कम हो सकता है, लेकिन सरकारों व कंपनियों को बड़े सुधार करने होंगे

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लोगों के छोटे-छोटे पर्यावरण अनुकूल कदम, जैसे कचरे का पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग), दोबारा इस्तेमाल होने वाले कप और डिब्बों का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन अपनाना, हरित आहार लेना और साइकिल से काम पर जाना, व्यापक जलवायु कार्रवाई के रास्ते में बाधा नहीं बनते बल्कि जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं। एक नए शोध में यह बात सामने आई है।

ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स (यूएनएसडब्ल्यू) के व्यवहार वैज्ञानिकों और ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने करीब 2,800 ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर चार साल तक अध्ययन किया। यह अध्ययन नेशनल क्लाइमेट एक्शन सर्वे के माध्यम से किया गया, जिसमें साल 2021 से 2024 तक लोगों के व्यवहार और जलवायु संबंधी सोच को समझा गया। अध्ययन एनपीजे क्लाइमेट एक्शन नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। जलवायु नीति का असली असर- 88 देशों और पांच अरब लोगों पर किए गए अध्ययन में क्या आया सामने?

अध्ययन में रिसाइक्लिंग, सार्वजनिक परिवहन और हरित जीवनशैली अपनाने वाले लोग व्यापक जलवायु कार्रवाई के विरोधी नहीं पाए गए। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प अपनाते हैं, वे बड़े स्तर पर जलवायु नीतियों और सामूहिक प्रयासों का समर्थन करने से पीछे नहीं हटते। लंबे समय से यह तर्क दिया जाता रहा है कि सरकारें और कंपनियां लोगों को छोटे व्यक्तिगत बदलावों पर ध्यान केंद्रित कराकर असली समस्या, यानी ऊर्जा व्यवस्था में बदलाव और बड़े उद्योगों पर नियंत्रण जैसे कदमों से ध्यान भटका सकती हैं। इस सोच के अनुसार, जब लोग खुद कुछ पर्यावरणीय काम कर लेते हैं तो वे बड़े बदलावों की मांग कम कर सकते हैं। शोध में यूएनएसडब्ल्यू इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट रिस्क एंड रिस्पॉन्स के शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि व्यक्तिगत जलवायु कार्रवाई न तो व्यापक जलवायु भागीदारी को बढ़ाती है और न ही उसे कमजोर करती है। उनके अनुसार, यह धारणा सही साबित नहीं हुई कि लोग छोटे व्यक्तिगत प्रयास करने के बाद यह मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और अब बड़े बदलावों की जरूरत नहीं है। शोध में यह भी देखा गया कि जो लोग पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक थे, वे आमतौर पर सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी ज्यादा सक्रिय थे। ऐसे लोग जलवायु से जुड़े अभियानों में भाग लेने, याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने और जलवायु नीतियों का समर्थन करने की अधिक संभावना रखते थे। या कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत पर्यावरणीय कदम बढ़ाने से अगले साल उसकी राजनीतिक भागीदारी अपने आप नहीं बढ़ी और न ही घटी। यह अध्ययन इस धारणा को चुनौती देता है कि केवल रिसाइक्लिंग जैसे छोटे काम लोगों को बड़े जलवायु बदलावों से दूर कर देते हैं। लेकिन यह भी साबित नहीं करता कि छोटे व्यक्तिगत कदम अपने आप लोगों को सामाजिक आंदोलन या नीतिगत बदलाव की ओर ले जाएंगे। शोधकर्ताओं का कहना है कि व्यक्तिगत प्रयास और बड़े स्तर पर होने वाले बदलाव एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। लोगों की आदतों में बदलाव जरूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ सरकारों और कंपनियों को भी ऊर्जा, परिवहन और उद्योगों में बड़े सुधार करने होंगे। अध्ययन में कहा गया है कि यह चिंता सही हो सकती है कि कुछ कंपनियां केवल उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव पर जोर देकर अपनी बड़ी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती हैं। इसलिए व्यक्तिगत कदमों को व्यापक नीतिगत बदलावों का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि 2021 से 2024 के बीच सामूहिक जलवायु कार्रवाई और जलवायु नीतियों के समर्थन में थोड़ी कमी आई। वहीं लोगों के व्यक्तिगत पर्यावरणीय व्यवहार लगभग स्थिर रहे। शोधकर्ताओं के अनुसार, इसका एक कारण बढ़ती जीवन-यापन लागत हो सकती है। जब लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है तो उनके पास सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने या ऐसी नीतियों का समर्थन करने के लिए कम समय और ऊर्जा बच सकती है, जिनसे उन्हें अतिरिक्त खर्च का डर लगता है। अध्ययन में रिसाइक्लिंग, सार्वजनिक परिवहन और हरित जीवनशैली अपनाने वाले लोग व्यापक जलवायु कार्रवाई के विरोधी नहीं पाए गए। इस अध्ययन का संदेश उन कंपनियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम चलाती हैं। कर्मचारियों या ग्राहकों को हरित आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना जलवायु कार्रवाई के समर्थन को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसे संगठनात्मक बदलावों का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। विशेषज्ञों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी और बड़े स्तर पर नीतिगत सुधार दोनों की जरूरत है। छोटे कदम लोगों की पर्यावरणीय सोच को दिखाते हैं, लेकिन पृथ्वी को बचाने के लिए व्यापक बदलाव भी उतने ही आवश्यक हैं।

आमजन की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए इंदौर जिले में चलेगा मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान

टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, अवैध कॉलोनियों, फायर सेफ्टी की समीक्षा

इंदौर,मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के अनुरूप इंदौर जिले में आमजन की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए मुख्यमंत्री जन?-विश्वास अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 7 अगस्त से प्रारंभ होकर आगामी 8 जनवरी 2027 तक चलेगा।

अभियान के अंतर्गत जमीनी स्तर पर पहुँचकर शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों तथा लोकसेवाओं की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। यह जानकारी कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आज सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई समय-सीमा के पत्रों (टीएल) के निराकरण की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, आगामी मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान, अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई, फायर सेफ्टी की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित झाड़े, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री नवजीवन विजय पवार, श्री रिंकेश वैश्य तथा श्री रोशन राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार इस शुक्रवार 7 अगस्त से प्रदेशभर में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान प्रारंभ हो रहा है। अभियान के सफल संचालन के लिए सभी विभाग पूरी तैयारी सुनिश्चित करें। प्रत्येक विभाग अपने दायित्वों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करे, रोस्टर बनाए तथा शिविरों के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जनविश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले शिविरों में संबंधित क्षेत्र की सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का प्रभावी निराकरण किया जाए। साथ ही शिविरों में प्राप्त होने वाले आवेदनों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008